पूरी बेंच

सिविल अपील

माननीय न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, एम आर शर्मा और हरबंस लाल के समक्ष,

जोखी राम,-अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती. नरेश कांता और अन्य, -प्रतिवादी।

1972 का प्रथम अपील आदेश क्रमांक 47

25 मार्च, 1977.

मोटर वाहन अधिनियम (4)1939)—धारा 110-ए और 110-बी—मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु—मुआवजे का आकलन—का तरीका—बताया गया—मृतक की विधवा और नाबालिग बच्चों के बीच मुआवजे का बंटवारा—नाबालिग बच्चे—चाहे केवल मुआवजे के हकदार हों बहुमत की उम्र

आयोजित,मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 110-बी के तहत मुआवजे का दायरा घातक दुर्घटना अधिनियम की तुलना में व्यापक है, और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देते समय न्यायालयों को केवल एक सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि मुआवजा मूल्यांकन "न्यायसंगत" होना चाहिए। एक घातक दुर्घटना में, वाहन की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण पीड़ित का जीवन समाप्त हो जाता है और जीवित आश्रित मृतक की कमाई से वंचित हो जाते हैं, इसके परिणामस्वरूप मानसिक और भावनात्मक पीड़ा होती है और पारिवारिक ताना-बाना टूट जाता है। क्षति के आकलन के लिए मार्गदर्शक सितारा यह है कि मृतक की वार्षिक कमाई, वेतन वृद्धि या पदोन्नति के रूप में संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए, उन लाभों की कटौती के बाद सुनिश्चित की जानी चाहिए जो परिणामस्वरूप आश्रितों को प्राप्त हो सकते हैं। मृत्यु का और वह रकम भी जो मृतक से अपने ऊपर खर्च करने की अपेक्षा की गई थी। इस अनुमानित आय को उन वर्षों की संख्या से गुणा किया जाना चाहिए जिनसे मृतक का जीवन कम होने का अनुमान है। इसका परिणाम मुआवजे की उचित पूंजीकृत राशि होगी जिसके लिए आश्रित हकदार हो सकते हैं। मृतक की उचित आय और अनुमानित कटौती का आकलन करने के उद्देश्य से कोई कठोर सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में, संबंधित परिवार के जीवन और परिस्थितियों से जुड़े कई कारक प्रभाव में होते हैं और उन पर ध्यान देना होगा। इससे अनुमान का एक तत्व भी शामिल होने की संभावना है, लेकिन उचित मुआवजे का आकलन करते समय उचित अनुमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि जंगली अटकलों को, जिसके लिए दावेदार हकदार हो सकते हैं। यह सिद्धांत कि मुआवज़ा उस ब्याज को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए जो बैंक में जमा करके अर्जित किया जा सकता है, हालाँकि, मुआवज़े का आकलन करने के उद्देश्य से एक अनम्य सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है, खासकर इन दिनों में जब क्रय शक्ति शर्तों में होती है तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद धन का ह्रास हो रहा है।

(पैरा 13 और 14)

अभिनिर्धारित किया गया कि मुआवजे की राशि निकालने का मूल सिद्धांत उचित कटौती की अनुमति देने के बाद मृतक की अनुमानित वार्षिक आय का पता लगाना है और इस राशि को आपके द्वारा गुणा करके पूंजीकृत करना है। मृतक की जीवन प्रत्याशा के अनुसार वर्षों की संख्या है छोटा कर दिया गया. इस पद्धति से निकाली गई राशि को किसी न किसी आड़ में कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी दुर्भाग्यपूर्ण मृतक के जीवित बचे नाबालिग बच्चों के मामले में, यह सोचना अवास्तविक और भ्रामक है कि जैसे ही बेटा वयस्क होने के बाद सूई ज्यूरिस बन जाता, मृतक की ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती और बेटियाँ निश्चित हो जातीं। भारत में प्रचलित रीति-रिवाजों, परंपराओं और संयुक्त परिवार प्रणाली के अनुसार, परिवार के मुखिया, जो रोटी कमाने वाला होता है, का बच्चों का भरण-पोषण करने और उन्हें शिक्षित करने का दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक कि बेटे अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं और अलग न हो जाएं। कमाई का स्रोत और बेटियों के मामले में, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। एक बार; आश्रितों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि की गणना की जाती है, जिसे विधवा और बच्चों के बीच विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह होना चाहिए। इस प्रकार किया जाए कि कुल राशि जीवित परिवार को प्राप्त हो।

(पैरा 16).

माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा संदर्भित मामला, डीएस तेवतिया को बड़ा झटका 13 मार्च, 1975 को मामले से जुड़े कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए खंडपीठ। पूर्ण पीठ में माननीय श्री न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, माननीय श्री न्यायमूर्ति एम आर शर्मा शामिल हैं और माननीय श्री न्यायमूर्ति हरबंस लाल ने अंततः 25 मार्च 1977 को योग्यता के आधार पर मामले का फैसला किया।

श्री सालिग राम सेठ की अदालत, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हिसार के आदेश, दिनांक 6 नवंबर, से पहली अपील,1971, रुपये की राशि का मुआवज़ा। उत्तरदाताओं के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 25,562 रुपये और यह राशि बीमा कंपनी द्वारा दो महीने के भीतर जमा की जाएगी और आगे आदेश दिया गया है कि डिफ़ॉल्ट रूप से, दावेदार तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ इसकी वसूली करेंगे। अदालत की डिक्री की तरह प्राप्ति की तारीख तक आदेश का।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एनसी जैन।

हरिंदर सिंह, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के लिए।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल,

(1) ये तीन अपीलें, एफएओ। 1972 के नंबर 47, 84 और 114, माननीय न्यायमूर्ति तेवतिया, (जैसा कि वह तब थे) के एक संदर्भ पर कानून के दो बिंदुओं के निर्धारण के लिए हमारे सामने हैं - उनके आदेश 13 मार्च,

1975 के तहत, और इनका निपटारा किया जाएगा एक ही निर्णय क्योंकि इन तीनों अपीलों के विरुद्ध दायर किया गया था; मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद इसे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) का निर्णय, दिनांक 6 नवंबर, 1971।

(2) मृतक श्री ओम प्रकाश शर्मा 28 जनवरी 1969 को सायं 7.30 बजे सूरत सिंह द्वारा संचालित मोटर साइकिल पर फतेहाबाद से टोहाना लौट रहे थे, भूना-फतेहाबाद रोड पर भूना से लगभग तीन मील की दूरी पर, एक शेर सिंह द्वारा संचालित और जोखी राम के स्वामित्व वाला ट्रक नंबर एचआरएच-9071 विपरीत दिशा से तेजी और लापरवाही से आया और मोटर साइकिल में टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप ओम प्रकाश शर्मा और सूरत सिंह की मौत हो गई। इस घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना भूना में दर्ज कराई गई थी। ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) की पत्नी श्रीमती नरेश कांता और उनके पांच नाबालिग बच्चों (चार बेटियां और एक बेटा) ने ट्रिब्यूनल के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 110-ए के तहत एक आवेदन दायर किया। मुआवजे की राशि रु. 1,40,000. ट्रक का बीमा वैनगार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया गया था। श्री जोखी राम, शेर सिंह और वैनगार्ड बीमा कंपनी को क्रमशः ट्रक के मालिक, चालक और बीमाकर्ता के रूप में प्रतिवादी बनाया गया था। तीनों उत्तरदाताओं ने दावे का विरोध किया। पार्टियों की दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:

1. क्या दुर्घटना ड्राइवर शेर सिंह की लापरवाही और लापरवाही के कारण हुई?
2. क्या याचिका समय पर है?
3. क्या शेर सिंह, ड्राइवर, घटना के समय ट्रक मालिक जोखी राम के रोजगार में था, और यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या होगा?
4. क्या याचिकाकर्ता किसी भी राशि के मुआवजे के हकदार हैं, यदि हां, तो कितनी राशि और किससे?
5. क्या याचिकाकर्ताओं के लिखित बयान में दिए गए कारणों से बीमा कंपनी उनके दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है?

6. राहत.

सभी मुद्दों का फैसला अपीलकर्ताओं (प्रतिवादियों) के खिलाफ किया गया। अंक संख्या 1 और 3 के संबंध में, यह माना गया कि दुर्घटना चालक शेर सिंह द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी, ट्रक का मालिक जोखी राम था और वह उस समय था, घटना के समय शेर सिंह ट्रक मालिक के यहां ड्राइवर की नौकरी करता था और ट्रक चला रहा था। अंक संख्या 2 पर भी आवेदकों के पक्ष में निर्णय लिया गया और आवेदन को समय के भीतर माना गया। अंक क्रमांक 5 बीमा कंपनी के विरुद्ध तय किया गया और उसे आवेदकों के दावे के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। मुद्दे संख्या 4 पर, न्यायाधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

1. ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में लाइन अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और 390 प्रति माह रुपये का वेतन प्राप्त कर रहे थे।; और

2. कि ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) की पत्नी को उनके पति की मृत्यु पर रु. की दर से पेंशन मिलती थी। 120 प्रति माह. रुपये काटने के बाद. घर के किराये के मद में प्रति माह 70 रु. मृतक के हिस्से के रूप में 37 रुपये प्रति माह और रु। अपने वेतन में से प्रति माह 60 रुपये स्वयं पर खर्च करते हैं। 390 प्रति माह, इसके अलावा 103 प्रति माह रु. मासिक पेंशन के कारण आवेदकों को 120 रुपये की हानि का आकलन किया गया।.

(3) ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) की आयु दुर्घटना के समय 37 वर्ष पाई गई और उनकी जीवन प्रत्याशा की गणना की गई 60 वर्ष की आयु में, 23 वर्षों के लिए 28,428 रुपये की दर से हर्जाना। प्रति माह 103 रुपये की गणना की गई।.

(4) ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) का बीमा रुपये में हुआ था। 2,000 रुपये की राशि उनकी मृत्यु के बाद आवेदकों को प्राप्त हुई। इस राशि का एक तिहाई हिस्सा छोड़कर, रु. हर्जाने की रकम से 666 रुपये की कटौती की गई। इसके अलावा, ग्रेच्युटी राशि रु. 2200 रुपये की कटौती भी की गई. इन सभी कटौतियों के बाद, ट्रिब्यूनल ने रुपये की राशि प्रदान की। आवेदकों को 25,562 रुपये दिए गए और बीमा कंपनी को यह राशि दो महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

(5) जोखी राम. ट्रक के मालिक शेर सिंह, उसके ड्राइवर और वैनगार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने ये तीन अलग-अलग अपीलें दायर की हैं, एफएओ संख्या 114/1972 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सूरी ने निम्नलिखित दो तर्क उठाए:

1. ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई मुआवजे की राशि अत्यधिक है। यह उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे बैंक में जमा करने पर आवेदकों को ओम प्रकाश शर्मा के निधन के कारण हुई मासिक आर्थिक हानि के बराबर मासिक ब्याज मिलेगा; और

2. मुआवजे की राशि की गणना के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला अनुचित है।

(6) पहले तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने सुरजीत सिंह और अन्य बनाम द को-ऑपरेटिव जनरल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड और अन्य (1974 पी.बी. लॉ रिपोर्टर, 353) और न्यू सूरज ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम एम में निर्णय पर भरोसा किया। एस रूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (एफएओ 145/68, 7 मई 1974) विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि ट्रिब्यूनल ने आवेदकों को आर्थिक नुकसान की गणना करते समय ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) के वेतन में भविष्य की वृद्धि के संबंध में कोई भत्ता नहीं दिया, न ही उनकी पदोन्नति की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में। आगे यह माना गया कि एक सरकारी कर्मचारी से आम तौर पर वार्षिक वेतन वृद्धि और सामान्य पदोन्नति की उम्मीद की जाती है और इस तरह, भविष्य में वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए भत्ता दिए बिना ब्याज सिद्धांत का आवेदन आवेदकों के मामले में अन्याय होगा।

(7) दूसरे तर्क के संबंध में, विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि ओम प्रकाश शर्मा (मृतक) का नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व, उनके वयस्क होने पर समाप्त हो गया और इसलिए, आर्थिक हानि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दुर्घटना से कम हुई मृतक की जीवन प्रत्याशा का आधार। इस

विवाद के समर्थन में, प्रकाश वाबी और अन्य बनाम दिल्ली दयाल बाग डेयरी लिमिटेड (1967 दुर्घटना दावा जर्नल 82), और सरला देवी और अन्य बनाम शरीफ देवी अग्रवाल और अन्य, (1968 दुर्घटना दावा जर्नल 163) पर भरोसा रखा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सूद एंड कंपनी, कुल्लू बनाम सुरजीत कौर और अन्य (1973 दुर्घटना दावा जर्नल 414) के रूप में रिपोर्ट किए गए पहले के फैसले में अपनी टिप्पणियों का संदर्भ देने के बाद यह राय दी थी कि मुआवजे की गणना का तरीका विद्वान वकील द्वारा सुझाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अतार्किक और चौंकाने वाले परिणाम आने की संभावना है और प्रकाश वती के मामले (3) (सुप्रा) में डिवीजन बेंच ने मामले पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया था और विपरीत दृष्टिकोण उनके सामने नहीं था। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि कानून के ये दो बिंदु कई मामलों में उत्पन्न होने की संभावना है और सामान्य महत्व और सार्वजनिक हित के हैं और इस तरह क्यू पूर्ण पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए, उन्हें निर्धारण के लिए संदर्भित किया गया पूर्ण पीठ. इन परिस्थितियों में हमें अंक संख्या 5 में उत्पन्न होने वाले नुकसान के आकलन और मुआवजे के संबंध में इन तीन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है।

(8) आवेदकों द्वारा आवेदन जिसमें से ये तीन अपीलें उत्पन्न हुई हैं, अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दायर किया गया था। मुआवज़ा ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 110-बी के तहत दिया जाना है, जिसमें प्रावधान है कि ट्रिब्यूनल को पक्षों को सुनने का अवसर देना चाहिए, दावे की जांच करनी चाहिए और इसके अलावा यह पुरस्कार "निर्धारित करने" के बाद दिया जाना चाहिए। मुआवज़े की राशि1 जो उचित प्रतीत होती है।" विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को बड़ी संख्या में समान मामलों में मुआवजे के आकलन के सवाल से निपटने का अवसर मिला है। अंग्रेजी घातक दुर्घटनाओं के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में क्षति के आकलन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अधिनियम, जिनके प्रावधान भारत में घातक दुर्घटना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, डेविस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड(1942 एसी 601.) में लॉर्ड राइट द्वारा निर्धारित किए गए थे, और विस्काउंट साइमन द्वारा बल और स्पष्टता के साथ बहाल किए गए थे। नेंस बनाम ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी लिमिटेड, (1951 एसी 601) इन निर्णयों के अनुसार, मृत व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा का अनुमान उसकी उम्र, शारीरिक स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं जैसी परिस्थितियों द्वारा उसके जीवन के समय से पहले निर्धारित होने की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरे, उसकी पत्नी के भविष्य के भरण-पोषण के लिए आवश्यक राशि का अनुमान उस राशि को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा जो वह अपने जीवन काल के दौरान उस पर खर्च करता था। तीसरा, अनुमानित वार्षिक राशि को व्यक्ति के अनुमानित जीवन काल के वर्षों की अनुमानित संख्या से गुणा किया जाता है और उक्त राशि को कम किया जाना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु पर देय एकमुश्त राशि के बराबर राशि प्राप्त की जा सके। चौथा, विधवा को उसकी संपत्ति में उसके हित में तेजी से होने वाले लाभ के लिए कटौती की जानी चाहिए, और पांचवें, यदि पति ने जीवन की पूरी अवधि जी ली है तो पत्नी की मृत्यु पहले होने की संभावना के लिए अतिरिक्त राशि में कटौती की जानी चाहिए। ; और यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधवा की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए पुनर्विवाह की संभावना है। उपर्युक्त निर्णयों पर विचार करने के बाद, गोबैद मोटर सर्विस लिमिटेड और अन्य बनाम आरएमके वेलुस्वामी और अन्य (एआईआर 1962 एससी 1) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने कहा, -

> “अनुमान के उक्त तरीके से यह देखा जाएगा कि गणना में कई असंभव चीजें शामिल हो जाती हैं। इसलिए, उत्तरदाताओं को होने वाली आर्थिक हानि की वास्तविक सीमा डेटा पर निर्भर हो सकती

> है जिसे सटीक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक रूप से एक अनुमान होना चाहिए, या आंशिक रूप से अनुमान भी होना चाहिए। संक्षेप में कहा गया है, सामान्य सिद्धांत यह है कि आर्थिक हानि का आकलन केवल एक तरफ भविष्य के आर्थिक लाभ के दावेदारों को होने वाले नुकसान और दूसरी तरफ मृत्यु के कारण किसी भी स्रोत से मिलने वाले किसी भी आर्थिक लाभ को संतुलित करके किया जा सकता है। , अर्थात, मृत्यु से आश्रित को होने वाले नुकसान और लाभ का संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(9) दिल्ली नगर निगम बनाम सुभगवंती, (एआईआर 1966 एससी 1750) में, सुप्रीम कोर्ट में उनका आधिपत्य डेविस के मामले (6) (सुप्रा) में लॉर्ड राइट की एक और टिप्पणी पर निर्भर था, जिसके अनुसार राशि का आकलन करने के उद्देश्य से लाभार्थियों को देय मुआवजा, मृतक जो मजदूरी कमा रहा था उसकी अनुमानित राशि के लिए भत्ता बनाने के बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मृतक अपने जीवनकाल के दौरान खुद पर खर्च कर रहा था और फिर शेष राशि को एकमुश्त राशि में बदल दिया जाना चाहिए। वर्षों के प्रयोजनों की निश्चित संख्या। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा इस फॉर्मूले के आधार पर मृतक की आय को 15 वर्ष की अवधि के लिए पूंजीकृत किया गया था। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी.

(10) टीएन सीके सुब्रमोनिया अय्यर और अन्य बनाम टी. कुन्हिकुट्टन नायर और अन्य (एआईआर 1970 एससी 376), इंग्लैंड में इस विषय पर विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने नुकसान का आकलन करने के लिए निम्नानुसार सिद्धांत तैयार किए:

> "नुकसान का आकलन करते समय, न्यायालय को मामले के उन सभी विचारों को बाहर करना चाहिए जो अटकल या कल्पना पर आधारित हैं, हालांकि कुछ हद तक अनुमान अपरिहार्य है।"

(11) टैफ वेले रेलवे कंपनी बनाम जेनकिंस (1913 एसी 1) में अपने फैसले में लॉर्ड हाल्डनेट ने कहा कि नुकसान का आकलन करते समय सोलेशियम नहीं दिया जा सकता क्योंकि घायल भावनाओं या भावना के आधार पर कोई नुकसान नहीं दिया जा सकता, लेकिन संभावित नुकसान मृतक के आश्रितों को निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

> "आधार वह नहीं है जिसे सोलेटियम कहा गया है, यानी घायल भावनाओं के लिए या भावना के आधार पर दी गई क्षति, बल्कि आर्थिक क्षति के मुआवजे पर आधारित क्षति है, लेकिन तब नुकसान संभावित हो सकता है, और यह बिल्कुल स्पष्ट है संभावित नुकसान को ध्यान में रखा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि यह इस प्रस्ताव से योग्य है कि किसी भी क्षति का आकलन करने से पहले बच्चे को यह दिखाया जाना चाहिए कि वह कुछ कमा रहा है। मैं क़ानून में उस प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक रूप से कोई आधार नहीं जानता या कानून के किसी सिद्धांत में जो लागू हो; न ही मुझे लगता है कि जब आप उनकी जांच करते हैं तो यह वास्तव में अधिकारियों द्वारा स्थापित किया जाता है, मैंने पहले ही संकेत दिया है कि मेरे विचार से वास्तविक प्रश्न वह है जिसे विल्स, जे., हमारे सामने उद्धृत मामलों में से एक में परिभाषित करते हैं, डाल्टन

बनाम साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, ((1958) 4 सीबी (एनएस) 296) आया या नहीं, क्या आर्थिक लाभ की उचित उम्मीद थी?"

इस आदेश को सीके सुब्रमण्यम अय्यर के मामले (10) (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, और यह माना गया था कि माता-पिता मृत नाबालिग बच्चे की संभावित सेवा के वर्तमान नकद मूल्य की वसूली के हकदार हैं और उन्हें पुरस्कार दिया जा सकता है। बच्चे के वयस्क होने के बाद अपेक्षित आर्थिक लाभ के नुकसान के लिए मुआवजा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त मामले में, ट्रिब्यूनल ने 8 वर्ष की आयु के मृत बच्चे के माता-पिता को हर्जाना दिया था। उन नुकसानों को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

(12) हिरप विरजी ट्रांसपोर्ट और अन्य बनाम बहराम बीबी (1971 दुर्घटना दावा जर्नल 458) में, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस विषय पर अंग्रेजी और भारतीय न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि घातक दुर्घटनाओं के मामलों में, क्षति भविष्य में सभी संभावनाओं और परिवर्तनों का अनुमान लगाकर आकलन करना होगा। भविष्य की सभी उचित संभावनाएं हमेशा मूल्यांकन में शामिल होंगी और इस तरह के अनुमान में विभिन्न अनिश्चित कारकों और संभावनाओं के संबंध में रिकॉर्ड पर सामग्री पर नुकसान का आकलन करते समय आवश्यक रूप से कुछ अनुमान शामिल होते हैं।

(13) उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1-ए और 2 के आधार पर क्षति के आकलन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विकसित किया है। धारा 1-ए के तहत, क्षति एक को देय है या उसमें उल्लिखित अन्य संबंध, जबकि बाद वाला खंड शिकायत किए गए गलत कार्य के कारण मृतक की संपत्ति को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान करता है। कभी-कभी, दो प्रावधानों के तहत लाभार्थी एक ही हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 110-बी के तहत मुआवजे का दायरा, घातक दुर्घटना अधिनियम की तुलना में व्यापक है, और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देते समय न्यायालयों को केवल एक सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि मुआवजे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। "अभी"। एक घातक दुर्घटना में, वाहन की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण पीड़ित का जीवन समाप्त हो जाता है और जीवित आश्रितों को मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के अलावा मृतक की कमाई से वंचित होना पड़ता है और पारिवारिक ताना-बाना टूट जाता है। क्षति के आकलन के लिए उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार मार्गदर्शक सितारा यह है कि मृतक की वार्षिक कमाई, वेतन वृद्धि या पदोन्नति के रूप में संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए, उन लाभों की कटौती के बाद सुनिश्चित की जानी चाहिए जो मृत्यु के परिणामस्वरूप आश्रितों को प्राप्त हो सकता है और वह राशि भी जो मृतक से अपने स्वयं पर खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। इस अनुमानित आय को उन वर्षों की संख्या से गुणा किया जाना चाहिए जिनसे मृतक का जीवन कम होने का अनुमान है। इसका परिणाम मुआवजे की उचित पूंजीकृत राशि होगी जिसके लिए आश्रित हकदार हो सकते हैं। मृतक की उचित आय और अनुमानित कटौती का आकलन करने के उद्देश्य से कोई कठोर सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में, संबंधित परिवार के जीवन और परिस्थितियों से संबंधित कई कारक क्रियान्वित होते हैं और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे अनुमान का एक तत्व भी शामिल होने की संभावना है, लेकिन जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उचित मुआवजे का आकलन करते समय उचित अनुमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि जंगली अटकलों को, जिसके दावेदार हकदार हो सकते हैं।

(14) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने मृतक की वार्षिक कमाई का अनुमान लगाने और मृत्यु के परिणामस्वरूप आवेदकों को होने वाली कटौती की अनुमति देने के बाद तर्क दिया कि मुआवजे के रूप में केवल वही राशि दी जानी चाहिए जो समान मासिक राशि प्राप्त करने में सक्षम हो। बैंकों द्वारा शुरू की गई विभिन्न बैंक योजनाओं के अनुसार, बैंक ब्याज के संबंध में। आवर्ती या सावधि जमा. इस विवाद के समर्थन में, परमिंदर सिंह बनाम मुक्तसर जनता कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य , जागीर कौर और अन्य बनाम मैसर्स पर भरोसा रखा गया है। उत्तम सिंह छत्तर सिंह और अन्य (1973 दुर्घटना दावा जर्नल, 116), सुखदेव राज जैन और अन्य बनाम शांति देवी और अन्य (1975 दुर्घटना दावा जर्नल, 26), और द न्यू सूरज ट्रांसपोर्ट कंपनी के मामले (2) (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें यह आयोजित किया गया था, —

> "श्री सूरी का तर्क है कि वह मानदंड सही नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा सही मानदंड निर्धारित किए गए हैं

सुरजीत सिंह और अन्यवी. सहकारी जनरल इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड और अन्य (1) (सुप्रा)। इस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि दावेदारों को एक पूंजीकृत राशि मिल रही है, इसलिए यह पता लगाने का तरीका कि उन्हें कितनी राशि मिलनी चाहिए, यह देखना है कि उस राशि पर कितना ब्याज मिलेगा और क्या वह ब्याज उन्हें मृतक से मिल रहे लाभ के बराबर है। , तो वह राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है और वास्तव में, हम अपने निर्णय से बंधे हैं। इसलिए, सुरजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्धारित मानदंडों को लागू किया जाना चाहिए।

श्री सूरी के अनुसार. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, इन निर्णयों के अनुपात के आधार पर, आवेदकों-प्रतिवादियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि 25,562 रुपये से कम लगभग रु. 12,000 या 15,000 रुपये की राशि की जानी चाहिए। यह सही है कि उपर्युक्त मामलों में बैंक में जमा करने पर मिलने वाले ब्याज को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया गया है। हालाँकि, इस ब्याज सिद्धांत को विशेष रूप से इन दिनों में मुआवजे का आकलन करने के उद्देश्य से एक अनम्य सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है जब मुद्रास्फीति के कारण थोड़े अंतराल के बाद पैसे के संदर्भ में क्रय शक्ति कम हो रही है।

(15) जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है, ट्रिब्यूनल द्वारा मृतक की मासिक आय का आकलन 103 रु. दावेदारों को नुकसान का आकलन करने के उद्देश्य से धारा बहुत कम है और गलत डेटा के आधार पर काम किया गया है। मृतक को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में लाइन अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी मृत्यु के समय वे 390 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे।. श्री अमर सिंह गुप्ता, लेखाकार, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, एडब्ल्यू 2 के बयान के अनुसार, यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो मृतक को एक उप-विभागीय अधिकारी और यहां तक कि एक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया जा सकता था। यह भी कहा गया कि एक उप-विभागीय अधिकारी का प्रारंभिक वेतन रु 450 प्रति माह और एक कार्यकारी अभियंता का वेतन रु. 800 प्रति माह. मृतक को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होना चाहिए। हालाँकि, पदोन्नति की इन संभावनाओं को, जिन्हें महज अटकलें नहीं कहा जा सकता, ट्रिब्यूनल द्वारा वार्षिक आय का आकलन करते समय विचार से बाहर रखा गया था।

दूसरी ओर, 120 रुपये की राशि, मृतक के मासिक वेतन से 120 प्रति माह पेंशन रुपये प्रति माह की कटौती इस आधार पर की गई कि उसकी विधवा को रुपये का पुरस्कार दिया गया था। । आवेदक श्रीमती नरेश कांता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पति की मृत्यु के कारण उन्हें दी गई पेंशन प्रति माह 120 रुपये सात साल तक और उसके बाद, उसे केवल 60 प्रति माह रुपये का भुगतान किया जाएगा। विधवा के इस बयान का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था। मैंने पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 का भी अध्ययन किया है, जिसके अनुसार एक विधवा मृतक की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से पहले सात वर्षों के लिए या उस तारीख तक, जिस दिन मृतक अपने घर पहुंचा होगा, सामान्य पेंशन को दोगुना करने की हकदार है। यदि वह जीवित रहता तो सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु, जो भी अवधि कम हो, और उसके बाद, सामान्य पेंशन, उसे देय होगी।

(16) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई पूंजीकृत राशि को विधवा और पांच नाबालिग बच्चों के बीच समान शेयरों में विभाजित किया जाना चाहिए। चूँकि नाबालिग बेटा केवल वयस्क होने की आयु तक, यानी 18 वर्ष की आयु तक और नाबालिग बेटियाँ 16 वर्ष की आयु तक मुआवजे की हकदार होंगी, उनके हिस्से को पूंजीगत राशि के अनुपात में कम किया जाना चाहिए। वार्षिक को गुणा करके निकाला गया 23 वर्षों की हानि जिससे मृतक का जीवन छोटा हो गया। इस तर्क के समर्थन में, प्रकाश वती के मामले और सरला देवी के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया गया है। पहले मामले में, ट्रिब्यूनल ने मृतक के बेटे को 18 साल की उम्र तक और मृतक की बेटियों को 16 साल की उम्र तक मुआवजा देने का फैसला किया था। फ़ालशॉ और मेहर सिंह, जे.जे. (जैसा कि वे तब थे), इस प्रकार आयोजित किया गया:

> "हालांकि बेटों के मामले में बालिग होने की उम्र तक हर्जाने की गणना के बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बेटियों के मामले में आजकल शादी के लिए 16 साल की उम्र कुछ हद तक कम लगती है।" और आजकल यह चलन है कि लड़कियों की शादी देर से की जाती है, यह उचित है कि बेटियों के मामले में भी नुकसान की गणना के लिए उम्र 18 वर्ष मानी जाए।"

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि शायद केवल वयस्कता की आयु तक के बच्चों को मुआवजे के बंटवारे के संबंध में पुरस्कार के औचित्य को चुनौती देने वाले विस्तृत तर्कों को संबोधित नहीं किया गया था और निर्णय समस्या पर किसी भी गंभीर दिमाग के आवेदन का संकेत नहीं देता है। सरला देवी के मामले (4) (सुप्रा) में, वयस्क होने तक के बच्चों के संबंध में मुआवजा तय करने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले को विद्वान एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा था और बिना किसी चर्चा के, केवल निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

> "जहां तक बच्चों को मुआवजा देने का सवाल है, इसमें किसी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है।"

सुरजीत कौर के मामले (5) (सुप्रा) में, तेवतिया, जे. (जैसा कि वह तब था) की राय थी कि नाबालिग बच्चों के मामले में वयस्कता की उम्र के सिद्धांत को लागू करके मुआवजे की गणना का तरीका अतार्किक हो जाएगा और चौंकाने वाले परिणाम विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, यदि कोई विधवा एकमात्र जीवित

आश्रित है, तो उसे अनुमानित वार्षिक हानि को उन वर्षों की संख्या से गुणा करने के बाद पूरी पूंजीकृत राशि प्रदान की जाएगी, जिससे मृतक का जीवन कम हो जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां मृतक के जीवित रहने पर न केवल उसकी विधवा, बल्कि उसके नाबालिग बच्चे भी जीवित रहते हैं, नाबालिग बच्चों को अलग से मुआवजा देने की आड़ में, विधवा का हिस्सा काफी कम कर दिया जाएगा और नाबालिग बच्चों को कुछ वर्षों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। उस समय उनकी आयु लगभग 16 या 17 वर्ष थी

दुर्भाग्यपूर्ण घातक दुर्घटना. नुकसान की गणना करने और मुआवजा देने की ऐसी पद्धति को "न्यायसंगत" नहीं माना जा सकता है और अधिनियम की धारा 110-बी के तहत इस तरह के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा माना गया है, मुआवजे की राशि निकालने का मूल सिद्धांत उचित कटौती की अनुमति देने और उसे पूंजीकृत करने के बाद मृतक की अनुमानित वार्षिक आय का पता लगाना है। इस राशि को उन वर्षों की संख्या से गुणा करके, जिनसे मृतक की जीवन प्रत्याशा कम हो गई है। इस पद्धति से निकाली गई राशि को किसी न किसी आड़ में कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी दुर्भाग्यपूर्ण मृतक के जीवित बचे नाबालिग बच्चों के मामले में, यह सोचना अवास्तविक और भ्रामक है कि जैसे ही बेटा वयस्क होने के बाद सूई ज्यूरिस बन जाता, मृतक की ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती और बेटियाँ निश्चित हो जातीं। 16 वर्ष की आयु के बाद विवाह होना। भारत में प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं और संयुक्त परिवार प्रणाली के अनुसार, परिवार के मुखिया, जो रोटी कमाने वाला होता है, का बच्चों का भरण-पोषण करने और उन्हें शिक्षित करने का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक कि बेटे अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं और अलग न हो जाएं। कमाई का स्रोत और बेटियों के मामले में, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। एक बार जब आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि तय हो जाती है, तो उसे विधवा और बच्चों के बीच बांटा जा सकता है, लेकिन यह इस तरह से किया जाना चाहिए कि कुल राशि जीवित परिवार को प्राप्त हो।

(17) जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, हमारी राय में, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को किसी भी तरह से अत्यधिक नहीं माना जा सकता है। बल्कि, यह निम्न स्तर पर है। चूँकि आवेदकों द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए हमें पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन पुरस्कार की राशि को ब्याज सिद्धांत के आधार पर या उसी के बंटवारे के आधार पर कम करने का विधवा और एक विशेष उम्र तक के बच्चों के बीच कोई मामला नहीं बनता है। ।

(18) अंत में, यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 95(2)(ए) के तहत, अपीलकर्ता बीमा कंपनी की अधिकतम देनदारी रु. 20,000, इस प्रावधान को 1969 के अधिनियम संख्या 56 द्वारा संशोधित किया गया था जिसके द्वारा ट्रकों के मामलों में बीमा कंपनी की अधिकतम देयता 20,000 से रु. 50,000 रुपये से बढ़ा दी गई थी। हालाँकि, यह संशोधन 2 मार्च, 1970 से लागू किया गया था, जबकि दुर्घटना 28 जनवरी, 1969 को हुई थी। इस प्रकार, विवाद सारहीन नहीं है, अपीलकर्ता बीमा कंपनी को 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस हद तक, ट्रिब्यूनल के फैसले को संशोधित करने की आवश्यकता है। हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं।

-

मैं

(19) ऊपर उल्लिखित कारणों से, इन तीन अपीलों को पुरस्कार के इस संशोधन के साथ खारिज कर दिया जाता है कि 25,562 रुपये में से, वैनगार्ड इंश्योरेंस कंपनी, केवल 20,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी और शेष राशि के लिए अन्य अपीलकर्ता उत्तरदायी होंगे। शूल्क के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

(20) मैं सहमत हूं कि अपील को इस संशोधन के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वैनगार्ड बीमा कंपनी केवल 20,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा